ancillaries etc. the effect of any specific brand name has not been studied. There is scope for expansion of this industry in the country.

(d) The growth rate of the industry as per information furnished by DGTD works out to be approximately 2.5 per cent per annum between 1981—1985 and whereas the same is approximately 5.5 per cent per annum between 1986—1990.

Addition of colour in Amul Butter

725. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state what are the reasons for permitting addition of colour in Amul Butter and refusing the same in Dalda Vanaspati Ghee?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): As per Directorate General of Health Services, Government of India, in Amul Butter which is a table butter, two natural colours, namely, Annatto and Carotene are permitted as per International practice. But in the case of Vanaspati addition of colouring matter is neither practicable nor desirable.

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों का पुनर्गठन किया जाना

726. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को उनमें भारी पूंजी निवेश के बावजूद लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योगों के मुकाबले में वाणिज्यिक रूप से प्रतियोगी सिद्ध नहीं हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी क्षेत्र के एकक निरंतर लाभ कमाते आ रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दोनों क्षेत्र के उद्योगों के संचालन, कार्यकरण, प्रशासन, उत्पादन कुशलता और बिक्री आदि का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ङ) क्या सरकार बदलती हुई अर्थ-मान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्गठन करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) वर्ष 1989-90 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 98 उद्यमों ने 1959.09 करोड़ रुपये का कुल घाटा उठाया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को संसद में प्रस्तुत औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्गठन करने के लिए उपायों की घोषणा पहले ही कर दी है ।

727. [*Transferred to the 3rd December*, 1991]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहकारी समितियों को सौंपा जाना

728. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय रुग्ण उद्योगों को कर्मचारियों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को सौंपने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है ; और